(ग) क्या सरकार का विचार कण्ट्रोल के कपड़े का मूल्य कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अन्सारी) .(क) और (ख). कण्ट्रोल के कपड़े की योजना के विभिन्न पहलुओं पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

(ग) कण्ट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमतें (1974 से स्थिर) पहले की उत्पादन लागतों से कम हैं इस लिए कण्ट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमतें को और कम करने का प्रश्न नही उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, पता नहीं मंत्री जी ने किस आधार पर यह कह दिया कि 1974 के बाद कण्ट्रोल के कपड़े की कीमतों में बढ़ोतरी नही हुई है । आप कहीं भी जा कर पता लगा सकते हैं, कीमते बढ़ी है, और दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । हमारे गरीबों के लिए कण्ट्रोल के कपड़े की कितनी जरूरत है, इस का हम सब को अहसास है और इसी लिए आप ने यह योजना चलाई थी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप यह बतला सकेंगे कि योजना के विभिन्न पहलुओं पर सरकार जो अध्ययन कर रही है, इस अध्ययन का काम कितने दिनों में समाप्त होगा और किन मुख्य बातों के बारे में अध्ययन कार्य चल रहा है ?

श्री जिया उर्रहमान अन्सारी :: जैसा मैंने अर्ज किया है, 1974 के बाद कण्ट्रोल के कपड़े की कीमतों में बढ़ोतरी नही हुई है । शास्त्री जी अगर कण्ट्रोल के कपड़े के अलावा दूसरे कपड़ों की बाबत कह रहे हों. .

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कण्ट्रोल के कपड़े के बारे में कह रहा हूं ।

श्री जिया उर्रहमान अन्सारी : कण्ट्रोल के कपड़े की कीमत नही बढ़ी है । 1974 में जो प्राइसेज थी, वही आज भी चली आ रही हैं, जिन को हम मिलों से खरीद कर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेंनल के जरिये उपभोक्ताओं को देते है ।

अब जहां तक यह सवाल है कि हम किन पहलुओं पर गौर कर रहे है और कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस में बहुत से मुख्तलिफ़ पहलू हैं । एक पहलू यह भी है कि कण्ट्रोल का जो कपड़ा बनता है, उस में हम कुछ सब्सीडी देते है और वह सब्सीडी जो हम देते हैं वह कास्ट आफ़ प्रोडक्शन और मार्केट में जिस भाव पर हम उस को बेचना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफेन्स है, उस को ध्यान में रख कर देते हैं ताकि कण्ट्रोल्ड क्लाथ प्रोड्यूस करने में जो मिलों को घाटा होता है, उस को पूरा किया जा सके और चीपर रेटस पर कपड़ा बेचा जा सके । अभी जो प्राइस एस्केलेशन होता है और इनपुट्स की कास्ट बढ़ने से जो कास्ट आफ़ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वह एक मसला है । इसकी वजह से हम पूरे तौर पर री-इम्बर्स नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण कुछ डिफीकल्टीज हमारे सामने आ रही हैं । इसी तरह से कुछ और भी मसले हैं और मैं शास्त्री जी को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और हमारी यह ख्वाहिश है कि हम कण्ट्रोल क्लाथ कम कीमत पर दे कर और खास तौर से वीकर सैक्शन आफ़ दि सोसाइटी को कण्ट्रोल्ड क्लाथ और चीपर क्लाथ उपलब्ध करा कर उन की खिदमत कर सकें । यह हमारी ख्वाहिश है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Soviet Buyers Boycotted Calcutta Tea Auction

*595. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Soviet buyers have boycotted Calcutta tea auction;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the boycott will entail loss to the trade and if so, the extent thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Soviet buyers kept out of Calcutta Auction only for sale No. 25 held on 16th and 17th June, 1980.

(b) More than a lakh chests of Tea worth approx. Rs. 8.6 crores meant for export to USSR were held up in exporters' warehouses due to agitation/Picketing by members of Calcutta Tea Workers' Board. The agitation of workers commenced from 12th May, 1980 and finally ended on 23rd June, 1980. The agitation/picketing of the workers prevented shipment of tea to the Soviet Union and as a result the

USSR decided to opt out of the Calcutta Auctions on 16th and 17th June, 1980.

(c) The absence of Soviet buyers resulted in some losses to the producers as the teas normally purchased by USSR were mostly withdrawn from sale No. 25 and those which were sold fetched lower prices due to lack of competition. The situation, however normalised from sale No. 26 held on 23/24th June 1980 when Soviet buyers resumed buying tea from Calcutta Auctions.

Shifting of Head Office of Visakhapatnam Steel Plant

*600. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the head office of the Visakhapatnam Steel Plant is at Delhi; and

(b) whether there is any proposal to shift it to Visakhapatnam?

THE MINISTER OF COMMERCE, AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). Visakhapatnam Steel Project (VSP) is a unit of Steel Authority of India Limited (SAIL) which has its Corporate Office at Delhi. The office of the General Manager, VSP was shifted to Visakhapatnam in September, 1975. Since then the Project Office has been functioning at Visakhapatnam.

Displaced persons around Bokaro Steel Ltd.

*601. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether he is aware of the movement of the persons displaced in the process of making colonies and factories for the Bokaro Steel Plant around that Plant resulting in several arrests this month;

(b) if so, facts thereof in detail; and

(c) what are the demands of the displaced persons and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). According to information received from the Bokaro Steel Plant, it appears that 72 persons who were trying to obstruct the construction activities on the road from Sectar IV to Sectar VIII were arrested by the local authorities beween the 18th June and 20th June, 1980. They have all since been released on bail. The situation is reported to be peaceful. It is not known whether the arrested were displaced persons or not. Though no demands have been placed before the Plant Managment, it appears that the agitation was launched on the said dates to seek fulfilment of the following main grievances:—

(a) All those displaced families who have not been benefited so far by the existing policy to offer employment opportunity to one person per family, should be offered employment in the company on priority basis.

(b) In the second phase, all such displaced person whose entire village would be demolished, should be given an additional employment per family and accordingly the existing employment policy regarding the displaced persons should be suitably modified.

(c) They claimed that earlier they were informed that their homestead land would not be acquired and even though subsequently their homestead land was acquired but their objections were not referred to appropriate authority. They further